गंगा एक्सप्रेस-वे को गति के लिए और 300 करोड़ मिले

- प्रयागराज से मेरठ तक बनेगा एक्सप्रेस वे
- अतिरिक्त व्ययभार के लिए 100 करोड़ दिए

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार प्रयागराज से मेरठ तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को और तेजी से पूरा कराने के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। जीएसटी का अतिरिक्त भार आने से 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। औद्योगिक विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

राज्य सरकार लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण करा रही है। इस काम को जल्द पूरा कराने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसीलिए औद्योगिक विकास विभाग परियोजना को और गति देने के लिए बचे हुए पैसे को जारी कर रहा है, जिससे देनदारियां जल्द निपटाई जा सकें। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 से जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इससे पीपीपी मॉडल पर बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेस-वे पर अतिरिक्त भार आया है। इसीलिए औद्योगिक विकास विभाग ने 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए हैं।

इसके साथ ही 200 करोड़ रुपये और दिए गए हैं। यह पैसा यूपीडा द्वारा एक्सप्रेस-वे बनाने वाली कंपनियों को तत्कालिक जरूरतों के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। यूपीडा का यह भी दायित्व है कि खर्च होने वाली धनराशि का ब्यौरा महालेखाकार प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आडिट के दौरान किसी तरह की कोई समस्या न आने पाए।